पृष्ठ एक के शेष ...

यूपीमें दीपावली...

बसों की मरम्मत और जरूरी कलपुर्जों की उपलब्धता पहले से सुनिश्चित करने को कहा गया है। त्योहार के दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों को विशेष परिस्थितियों को छोड़कर छुट्टी नहीं दी जाएगी। बस अड्डों पर साफ-सफाई, पीने के पानी, बैठने, डिजिटल समय सारिणी और सहायता केंद्र की व्यवस्था भी की जाएगी। परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक प्रभु नारायण सिंह ने बताया कि 11 दिन ड्यूटी करने वाले चालकों और परिचालकों को 4400 रुपये तथा 12 दिन ड्यूटी करने पर 4800 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसके लिए प्रतिदिन औसतन 300 किलोमीटर बस चलाना अनिवार्य होगा। संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को निर्धारित दूरी से अधिक संचालन पर 55 पैसे प्रति अतिरिक्त किलोमीटर भी मिलेंगे।

दिल्लीमें होने...

तेलंगाना और पंजाब सहित विभिन्न राज्यों से आने वाले लोगों को गृह मंत्री अमित शाह के इशारे पर रोकने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इसके बावजूद रैली में शामिल होने वाले लोगों की तादाद से देशवासियों में व्याप्त भारी आक्रोश का पता चलेगा। राहुल गांधी ने कहा कि देश में बहुत ज्यादा गुस्सा और गहरा भावनात्मक दर्द है, क्योंकि लाखों लोगों से वोट देने का अधिकार छीना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, उद्योगपति अडानी व अंबानी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के लाभ के लिए जनता के वोट चुराए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि विपक्ष का यह आंदोलन अलग-अलग विरोध प्रदर्शन नहीं, बल्कि एक साझा लड़ाई है।

बद्रीनाथ...

हुआ। हादसे की सूचना मिलते ही सेना, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस और राज्य आपदा प्रतिवादन बल (एसडीआरएफ) की टीमें मौके पर पहुंच गईं। राहत एवं बचाव अभियान शुरू कर दिया गया है। मृतकों के शवों को दुर्गम जंगल से सड़क तक लाने की कार्रवाई की जा रही है।

वाराणसी-दिल्ली...

वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस भारतीय रेलवे की प्रीमियम रात्रिकालीन सेवाओं की नई कड़ी है। अब तक वंदे भारत ट्रेनें मुख्य रूप से दिन में चलने वाली चेयरकार सेवाओं के रूप में संचालित होती रही हैं। स्लीपर संस्करण को लंबी दूरी की यात्रा को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिससे यात्री रात में आराम से सफर कर सुबह अपने गंतव्य तक पहुंच सकेंगे।

यूपीमें गुप्त...

मंत्रालय ने बताया डीआरआई को इस गुप्त ठिकाने के बारे में पुख्ता खुफिया जानकारी मिली थी। इसी आधार पर यूपी एटीएस की एक बड़ी संयुक्त टीम ने 29 को तड़के संदिग्ध ठिकाने पर अचानक छापेमारी की। मौके से टीम ने लगभग 184 किलोग्राम अर्ध-निर्मित ड्रग्स, करीब 582 किलोग्राम कच्चे रसायन और भारी मात्रा में ड्रग्स बनाने के आधुनिक उपकरण जब्त किए। आरोपियों के पास से लगभग 15.4 किलोग्राम तैयार मेथाक्वालोन, 153 किलोग्राम अन्य रसायन और ड्रग्स निर्माण में इस्तेमाल होने वाली एक मशीन बरामद की गई। इसके अलावा, एक अन्य आरोपी के ठिकाने से 168 किलोग्राम कच्चे रसायनों की एक और बड़ी खेप जब्त की गई।

९.३४...

एक सदस्य को प्रतिवर्ष छह हजार रुपये की आर्थिक सहायता दो-दो हजार रुपये की तीन किस्तों में प्रदान किए जाने की व्यवस्था है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट 'एक्स' पर पोस्ट कर दीपावली से पहले मिले उस उपहार के लिए उत्तर प्रदेश के अन्नदाता किसानों की तरफ से प्रधानमंत्री का आभार जताया। मुख्यमंत्री ने लिखा कि किसानों की खुशहाली में गांवों की समृद्धि और गांवों की समृद्धि में राष्ट्र की प्रगति निहित है। इसी संकल्प के साथ आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने गुजरात के बनासकांठा से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 24वीं किस्त के अंतर्गत देश के 9.34 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में 18,690 करोड़ रुपये से अधिक की सम्मान राशि सीधे अंतरित की।

सौरव दास...

जी. अरुल मुरुगन की खंडपीठ ने शुक्रवार को इस जनहित याचिका पर सुनवाई की। पीठ ने सौरव दास, केंद्र सरकार और अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए उनका जवाब मांगा है। अदालत ने मामले को छह सप्ताह बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। यानी अब संबंधित पक्षों को याचिका में लगाए गए आरोपों और मांगों पर अपना पक्ष रखना होगा। यह याचिका तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले के रहने वाले गणेश कुमार ने दायर की है। इसका शीर्षक गणेश कुमार बनाम क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी है। याचिकाकर्ता ने अदालत से दास की पहचान, राष्ट्रीयता और उनके पारिवारिक इतिहास की जांच कराने की मांग की है।

यूपी : एसआईआर...

उचित कार्रवाई करने और उसकी रिपोर्ट पेश करने को कहा। पीठ में न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना भी शामिल थे। अदालत ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि वे उन मामलों का ब्योरा चुनाव आयोग को दें, जिनमें कथित गड़बड़ियों की शिकायतों का अब तक निपटारा नहीं हुआ है।सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश के एक विधानसभा क्षेत्र में एक खास समुदाय के लोगों के नाम मतदाता सूची से हटवाने के लिए 32 फॉर्म-7 जमा किए गए थे। उन्होंने दावा किया कि कुछ फॉर्म पर बूथ लेवल ऑफिसर के हस्ताक्षर भी मौजूद हैं।याचिकाकर्ताओं ने चुनाव आयोग के हलफनामे में दी गई जानकारी पर भी सवाल उठाए। उनका कहना था कि आयोग की ओर से दी गई जानकारी में कई अंतर हैं, जिनकी जांच जरूरी है।चुनाव आयोग की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता डीएस नायडू ने स्वीकार किया कि बड़ी संख्या में फॉर्म-7 जमा किए गए थे। हालांकि, उन्होंने अदालत को बताया कि आयोग के अधिकारियों ने इन फॉर्म की जांच की थी और उन्हें गलत पाया था।

स्वदेशी...

यह परीक्षण 29 अक्टूबर 2026 को किया गया।यह राफेल मरीन फ्रेंच नेवी का लड़ाकू विमान है। इसे फ्रेंच पायलट उड़ा रहे थे। इन ट्रायल्स से भारतीय नौसेना में राफेल मरीन विमान को ऑपरेशनल बनाने की प्रक्रिया शुरू होगी। भारत को अभी तक राफेल मरीन मिला नहीं है। इस सफल परीक्षण के साथ ही राफेल मरीन विमान को भारतीय नौसेना में ऑपरेशनल यानी परिचालन रूप से शामिल करने की दिशा में शुरुआती कदम बढ़ा दिया गया है। इस परीक्षण को विमानवाहक पोत पर इसकी क्षमता परखने की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है।

यूपीमें...

कार्यालय में स्थानांतरित किया गया है। शशि कुमार को विशेष कार्याधिकारी, राहत आयुक्त कार्यालय से उपजिलाधिकारी, फतेहपुर नियुक्त किया गया है। सुशील कुमार सिंह को उपजिलाधिकारी, मथुरा से उपजिलाधिकारी, फतेहपुर भेजा गया है। हेमन्त कुमार चौधरी को उपजिलाधिकारी, पीलीभीत से विशेष कार्याधिकारी, उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में भेजा गया है। मांधाता प्रताप सिंह को विशेष कार्याधिकारी, उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से उपजिलाधिकारी, पीलीभीत बनाया गया है। मयंक गोस्वामी को उपजिलाधिकारी, पीलीभीत से बंदोबस्त अधिकारी (चकबंदी), चकबंदी मुख्यालय लखनऊ पदस्थ किया गया है।

तीसरी बार..

कि सपा-कांग्रेस मैच हारने के बाद अंपायर पर आरोप लगा रहे हैं कि वोट चोरी हुई। भाजपा संसद में चर्चा के लिए तैयार है। एक बार आ आइए विशेष सत्र बुलाते हैं। हम एक एक बात का जवाब देने को तैयार हैं। संसद में चर्चा कीजिए।अमित शाह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल की प्रशंसा करते हुए कहा कि मैं योगी जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने कठोर शासन देकर यूपी को माफियाओं से मुक्त किया है। यूपी से भाजपा को कोई हिला नहीं सकता है। उन्होंने कार्यकर्ताओं का आह्वान करते हुए कहा कि आप सब कमर कस लो। अर्जुन की तरह मछली की आंख पर नजर रखो हमें तीसरी बार सरकार बनानी है।उन्होंने कहा कि 2014 में यूपी में हमारे केवल 44 विधायक थे तब बहुत निराशा थी। मैं तहसील तक गया। एक बार संगठन ठीक हो गया तो 2014 में यूपी में 41 प्रतिशत वोट के साथ 73 सीटें जीतीं। 2016 में नोटबंदी हुई थी तो अखिलेश यादव को रात भर नींद नहीं आई थी। हमने 40 प्रतिशत वोट लेकर 312 सीट जीती थीं।इसके पहले, यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में भाग लेने के लिए गृहमंत्री अमित शाह आज लखनऊ पहुंचे। एयरपोर्ट पर उनका स्वागत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने किया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक भी मौजूद रहे। डॉ. राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय के सभागार में प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की अध्यक्षता में हो रही बैठक का शुभारंभ गृहमंत्री अमित शाह ने किया। बैठक में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्या, विनोद तावड़े, स्मृति ईरानी, जितिन प्रसाद व अन्य भाजपा के नेता, मंत्री, सांसद और विधायक मौजूद हैं।अपने स्वागत भाषण में बैठक को संबोधित करते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने भाजपा के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं का आह्वान करते हुए कहा कि आज आयोजित प्रदेश की कार्यसमिति में हम सब केवल एक औपचारिक बैठक में एकत्र नहीं हुए हैं बल्कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के संगठन की शक्ति का मूल्यांकन करने, अपनी उपलब्धियों की समीक्षा करने के साथ ही भविष्य की दिशा तय करने नई ऊर्जा और नए संकल्प के साथ प्रदेश में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनाने के लिये एकत्रित हुए हैं। पिछली बार हम भाजपा के कार्यकर्त्ता लोकसभा चुनाव 2024 के संपन्न होने के उपरांत 14 जुलाई 2024 को इसी सभागार में एकत्रित हुए थे। संगठन रचना के बाद आज पहली बार हम यहां मिल रहे हैं।

यूपीमें हो रही बारिशसे प्रभावितोंको तत्काल राहत देने का मुख्यमंत्री योगी का निर्देश



लखनऊ (हि.स.)। उत्तर प्रदेश में हो रही बारिश को लेकर सरकार सतर्क है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बारिश से प्रभावितों को तत्काल राहत देने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी ने शुक्रवार को जारी निर्देश में कहा कि अतिवृष्टि से हुई, आर्थिक हानि, पशुहानि पर तत्काल मुआवजा दिया जाए। बारिश में जिनके घर गिरे, उन्हें तत्काल अनुमन्य मुआवजा उपलब्ध कराएं। फसल बर्बादी का तत्काल आकलन कर किसानों को यथाशीघ्र मुआवजा दें। यह भी ध्यान रखा जाए कि घर गिरने से बेघर हुए लोगों को तत्काल राहत केंद्र और शरणालय केंद्र पहुंचाएं। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि वरिष्ठ अधिकारी फील्ड में रहकर प्रभावित परिवारों से संवाद करें। प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता तत्काल उपलब्ध कराएं। राहत कार्यों में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उल्लेखनीय है कि गुरुवार की शाम से ही उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम खराब है। कहीं तेज बारिश हो रही है तो कहीं लगातार बूंदा-बांदी हो रही है।

गोरखपुर को योगी कल देंगे 1663 करोड़ की सौगात

गोरखपुर (हि.स.)। गोरखपुर की बदलती तस्वीर और आधुनिक बुनियादी ढांचे के संकल्प को गति देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दीपावली से एक सप्ताह पहले ही, एक नवंबर को जिले को करीब 1663 करोड़ रुपये की लागत वाली 88 विकास परियोजनाओं का दीपावली उपहार देने जा रहे हैं। इन परियोजनाओं में रोड कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, नगरीय जीवन सुगमता, बाढ़ से जुड़े महत्वपूर्ण कार्य शामिल हैं। सीएम योगी, चौरीचौरा क्षेत्र को जाम से मुक्ति दिलाने वाले महत्वपूर्ण रेल ओवरब्रिज का लोकार्पण करने के साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर, बाढ़ बचाव, गोरखपुर शहर के जलभराव और सीवर प्रबंधन से संबंधित गोड़धोइया नाला परियोजना फेज एक का लोकार्पण और परियोजना के फेज दो, नाले के समानांतर सड़क और गोरखपुर सीवरेज योजना जोन ए 3 का शिलान्यास करेंगे।

छह राज्यों और दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण की समयसीमा बढ़ी

नयी दिल्ली (आससे.)। भारत निर्वाचन आयोग ने महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा, नगालैंड और दिल्ली में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का कार्यक्रम बढ़ा दिया है। आयोग के अनुसार, महाराष्ट्र में दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 13 नवंबर कर दी गई है। यहां इनके निस्तारण की प्रक्रिया 25 नवंबर तक चलेगी। नगालैंड में भी दावे-आपत्तियों के निस्तारण की अवधि 25 नवंबर तक रहेगी। आंध्र प्रदेश और हरियाणा में यह प्रक्रिया 20 नवंबर तथा तेलंगाना में 26 नवंबर तक चलेगी। इन पांच राज्यों में अंतिम मतदाता सूची 30 नवंबर को प्रकाशित होगी। वहीं, दिल्ली में दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 25 नवंबर कर दी गई है।

लाइव सुनवाई के वीडियो का गलत इस्तेमाल करने वालों पर होगी कारवाई

नयी दिल्ली (आससे.)। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के वीडियो और ऑडियो को सोशल मीडिया पर बिना अनुमति इस्तेमाल करने, उनमें बदलाव करने और उनसे कमाई करने के मामलों पर अदालत ने सख्त रुख अपनाया है। शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार से कहा है कि लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान रिकॉर्ड की गई अदालती कार्यवाही के वीडियो का अनधिकृत इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान नई नीति में शामिल किया जाए। अदालत का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि सुनवाई के वीडियो को तोड़-मरोड़कर पेश न किया जाए और उनका इस्तेमाल निजी प्रचार या कमाई के लिए न हो। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने शुक्रवार को केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि प्रस्तावित नीति में नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के जरूरी उपाय शामिल किए जाएं। इस पीठ में जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना भी शामिल थे। अदालत ने यह निर्देश तब दिया, जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि विभिन्न हाईकोर्ट और दूसरे संबंधित पक्षों से सुझाव मिल चुके हैं। इन सुझावों को इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) को भेज दिया गया है। मंत्रालय इन पर विचार करके व्यापक दिशा-निर्देश तैयार करेगा। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि मंत्रालय कुछ दिनों में अपना जवाब दे सकता है और मामले को दिवाली की छुट्टियों के बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया। सुप्रीम कोर्ट ने 24 जुलाई को निर्देश दिया था कि उसकी या हाईकोर्ट की सुनवाई के ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग को बिना अनुमति निकालना, साझा करना, अपलोड करना, दोबारा पोस्ट करना, प्रसारित करना, उसमें बदलाव करना या उससे कमाई करना प्रतिबंधित होगा। इसके अलावा ऐसी रिकॉर्डिंग को डिजिटल मंचों पर संग्रहित करने या होस्ट करने पर भी रोक लगाई गई थी। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के महासचिव या संबंधित हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल की पूर्व अनुमति जरूरी बताई गई थी। 18 सितंबर को अदालत ने इन निर्देशों को स्पष्ट करते हुए कहा था कि इसका मतलब यह नहीं है कि मान्यता प्राप्त समाचार संस्थानों को अदालती कार्यवाही की खबरें देने से रोका जा रहा है। समाचार संस्थान सुनवाई और कानूनी घटनाक्रम की रिपोर्टिंग कर सकते हैं, लेकिन वे अपनी खबरों में सुनवाई के ऑडियो-वीडियो क्लिप का इस्तेमाल नहीं कर सकते।

सुनवाई के दौरान अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने भी अदालत के सामने एक सुझाव रखा। उन्होंने कहा कि अदालत की ओर से जारी किए जाने वाले हर आधिकारिक वीडियो पर ऐसा डिजिटल हस्ताक्षर या वॉटरमार्क होना चाहिए, जिसकी सत्यता की जांच की जा सके। इससे आम लोग और डिजिटल मंच यह पहचान सकेंगे कि कौन-सा वीडियो असली है और किसके साथ छेड़छाड़ की गई है। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि अदालत की सभी कार्यवाहियों के वीडियो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर प्रमाणित और वॉटरमार्क वाले रूप में उपलब्ध कराए जाएं।

पत्नी की हत्या मामले में पति को आजीवन कारावास, अर्थ दंड

डेहरी ऑन सोन (आससे.) नौहट्टा थाना के टीपा गांव में पत्नी ज्योति सिंह की हत्या के मामले में सासाराम न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 14 प्रहलाद कुमार ने रोहतास जिले के नौहट्टा थाना कांड संख्या-26/22 में अभियुक्त पति पंकज सिंह उर्फ पंकज कुमार को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।न्यायालय ने धारा-302 भादवि में दोषी पाते हुए पंकज सिंह को आजीवन कारावास तथा दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा दी है। अर्थदंड न जमा करने पर छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। वहीं धारा-25(1-बी)ए आर्म्स एक्ट में दो वर्ष का कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माना, न देने पर एक माह की अतिरिक्त सजा तथा धारा-27 आर्म्स एक्ट में तीन साल का कारावास एवं पांच हजार रुपये जुर्माना, न देने पर एक माह की अतिरिक्त सजा सुनाई गई है। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।मालूम हो कि गत 18 फरवरी 2022 को सुबह करीब वादी अभियुक्त के पिता नौहट्टा बाजार में थे। तभी उनके पुत्र व कांड के प्राथमिक अभियुक्त पंकज सिंह ने सूचना दी कि उसने अपनी पत्नी को गोली मार दी है।

सील अस्पतालों को नये नाम से चलाने और अवैध वसूली के मामले में सरकार सख्त

लखनऊ (आससे.)। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे उन वीडियो और खबरों का गंभीरता से संज्ञान लिया है जिनमें लखनऊ, कानपुर और उन्नाव में पूर्व में सील किए गए

उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठकने एक सप्ताह में मांगी जांच रिपोर्ट

अस्पतालों को नए नाम से संचालित किए जाने और मरीजों से अवैध वसूली किए जाने के आरोप सामने आए हैं। उप मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को इस प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को सख्त निर्देश दिए हैं कि स्वास्थ्य महानिदेशालय स्तर से तीन सदस्यीय जांच टीम गठित कर पूरे मामले की गहन जांच कराई जाए। उन्होंने निर्देशित किया कि जांच आख्या के साथ-साथ दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध की जाने वाली कार्रवाई का प्रस्ताव एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराया जाए। उप मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि जनमानस के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने तथा विभाग एवं सरकार की छवि धूमिल करने वाले मानकविहीन और सील किए गए चिकित्सालयों का अवैधानिक संचालन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सील अस्पतालों को नए नाम से संचालित करने, मरीजों से अवैध वसूली करने तथा इस पूरे प्रकरण में संलिप्त पाए जाने वाले लोगों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। उप मुख्यमंत्री ने स्पष्ट संदेश दिया है कि उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर मरीजों का शोषण करने और कानून से खिलवाड़ करने वालों के लिए कोई जगह नहीं है।

असंगठित और गिग वर्कर्स के सामाजिक सुरक्षा बोर्ड का गठन की अधिसूचना जारी

नयी दिल्ली (आससे.)। केंद्र सरकार ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के गठन की अधिसूचना जारी कर दी है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री बोर्ड के अध्यक्ष होंगे।

इसमें केंद्र और राज्य सरकारों, एग्रीगेटर कंपनियों, नियोक्ताओं, सामाजिक संगठनों, श्रमिक संघों तथा गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के प्रतिनिधि शामिल होंगे। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अनुसार, बोर्ड का मुख्य उद्देश्य इन श्रमिकों के लिए लक्षित कल्याणकारी योजनाएं तैयार करने, उनकी निगरानी करने और सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाना है। बोर्ड केंद्र सरकार को विभिन्न श्रेणियों के श्रमिकों के लिए योजनाएं बनाने की सिफारिश करेगा। साथ ही, कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा, राज्यों में रिकॉर्ड रखने की व्यवस्था और संबंधित कोष के खर्च की निगरानी भी करेगा।

राज्यसभा के पूर्व सदस्य, समाजसेवी व उद्योगपति आरके सिन्हा का निधन

नोएडा(हि.स.)। राज्यसभा के पूर्व सदस्य, भाजपा के वरिष्ठ नेता, समाजसेवी तथा देश के प्रसिद्ध उद्योगपति आरके सिन्हा का शुक्रवार को नोएडा के सेक्टर 92 स्थित आवास पर निधन हो गया। शहर के कई बड़े नेता और समाजसेवी श्रद्धांजलि देने उनके घर पहुंचे। आज उनका पार्थिव शरीर हवाई मार्ग द्वारा पटना ले जाया जा रहा है। उनका अंतिम संस्कार शनिवार को किया जाएगा। पूर्व राज्यसभा सांसद की सहयोगी रहीं रत्ना सिन्हा ने बताया कि आरके सिन्हा वर्ष 2025 के जनवरी माह में ब्रेन स्ट्रोक से ग्रसित हो गए थे। उन्हें उपचार के लिए सिंगापुर ले जाया गया था। वहां उपचार के बाद नोएडा के सेक्टर 92 स्थित आवास पर रहने आ गए थे, जहां आज सुबह उनका निधन हो गया।

उन्होंने बताया कि आज शाम 7 बजे उनका पार्थिव शरीर दिल्ली से पटना ले जाया जाएगा। कल शनिवार सुबह 9.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक पटना स्थित अन्नपूर्णा भवन, पाटलिपुत्र में उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। दोपहर 12.00 बजे अन्नपूर्णा भवन से उनकी अंतिम यात्रा दीघा घाट के लिए प्रस्थान करेगी। बिहार में भोजपुर जिले के बहियारा गांव निवासी रविन्द्र किशोर सिन्हा का जन्म 22 सितम्बर 1951 को हुआ था। डॉ सिन्हा एसआईएस समूह के संस्थापक और चेयरमैन थे। राजनीति के साथ-साथ उद्योग जगत में उनकी विशिष्ट पहचान थी। भाजपा के शुरुआती दौर से जुड़े रहे डॉ सिन्हा ने पार्टी और संगठन के लिए लंबे समय तक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत पत्रकारिता से की थी। राजनीति विज्ञान और कानून की पढ़ाई करने वाले आरके सिन्हा की लेखन में गहरी रुचि थी। पत्रकारिता के दौर में उन्होंने 'जनांदोलन' नाम की किताब लिखी थी। इस किताब में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में चले छात्र आंदोलन का विस्तार से जिक्र किया गया।

एसपी ने लगाया जनता दरबार, सुनी फरियादियों की शिकायतें

डेहरी ऑन सोन (आससे.)। पुलिस अधीक्षक रोहतास द्वारा शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जनता दरबार आयोजित कर जनसुनवाई की गई। जनता दरबार में कुल 10 परिवादियों ने अपनी शिकायतें लेकर एसपी के समक्ष उपस्थित हुए। एसपी ने एक-एक कर सभी फरियादियों की समस्याओं को गंभीरता से सुना। शिकायतें मुख्य रूप से भूमि विवाद, मारपीट, धोखाधड़ी और पारिवारिक विवाद से संबंधित थीं।एसपी ने शिकायतों के त्वरित और निष्पक्ष निस्तारण के लिए संबंधित थाना अध्यक्षों एवं पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक शिकायत पर निर्धारित समय सीमा में काररवाई कर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।एसपी ने बताया कि जनता दरबार का उद्देश्य आम लोगों को न्याय सुलभ कराना और पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ाना है।

बंगाल में राजनीतिक हिंसा में जान गंवाने वालों के परिवारों को नौकरी देंगे शुभेंदु अधिकारी

कलकत्ता (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल सरकार राज्य में पिछले 25 सालों के दौरान चुनावी और चुनाव के बाद हुई राजनीतिक हिंसा में मारे गये लोगों के पात्र परिजनों को सरकारी नौकरी देने की योजना बना रही है। एक समाचार के मुताबक, राज्य सचिवालय 'नबन्ना' से जुड़े सूत्रों की मानें तो प्रस्तावित नीति के तहत पीड़ित परिवार के एक पात्र सदस्य को सरकारी रोजगार देने पर विचार किया जाएगा। इस योजना के दायरे में लोकसभा, विधानसभा और पंचायत चुनावों के दौरान या उनके बाद हुई हिंसा में जान गंवाने वालों के परिवारों को शामिल किया जाएगा। सरकार की इस पहल में पिछले ढाई दशकों के दौरान हुए सभी प्रमुख चुनावों को कवर किया जाएगा। इसमें विशेष रूप से चुनाव के बाद हुई हिंसा में मारे गए लोगों के पीड़ित परिवार। इसके अलावा 2019 लोकसभा चुनाव के बाद हिंसा से प्रभावित परिवार। राज्य में समय-समय पर हुए स्थानीय निकाय और पंचायत चुनावों के दौरान हुई हिंसक झड़पों के शिकार हुए लोग भी इसमें शामिल होंगे। सूत्रों के मुताबिक, योजना के क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार जल्द ही एक आधिकारिक विज्ञापन जारी करेगी। विज्ञापन प्रकाशित होने के बाद प्रभावित परिवारों को अपने-अपने जिला प्रशासन के माध्यम से आवेदन करना होगा। आवेदकों को अपने परिवार के सदस्य की मौत की परिस्थितियों, घटना की तारीख, स्थान और घटना कैसे हुई इसकी पूरी जानकारी और दस्तावेज देने होंगे।

जिला प्रशासन और सरकारी अधिकारियों की एक टीम आवेदनों की गहन जांच और दावों का भौतिक सत्यापन करेगी। जांच सही पाए जाने पर ही परिवार के किसी एक सदस्य को नौकरी का नियुक्ति पत्र दिया जाएगा।

राज्य सचिवालय के उच्च पदस्थ सूत्रों ने पुष्टि की है कि इस नीतिगत प्रस्ताव को पश्चिम बंगाल कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। इसके अलावा, राज्य के कानून विभाग ने भी इस योजना को हरी झंडी दे दी है।गंभीर राजनीतिक हिंसा के दंश को झेल चुके परिवारों को आर्थिक राहत और सहारा देने के मकसद से लाई जा रही इस योजना का औपचारिक ऐलान सरकार की ओर से बहुत जल्द किए जाने की उम्मीद है।

जम्मू-कश्मीरमें लश्कर-टीआरएफ से जुड़े 10 गिरफ्तार

पैसे जुटाकर आतंकियों तक पहुंचाते थे, 68 दिनों में 28 आतंकी सहयोगी गिरफ्तार

जम्मू-कश्मीर (आससे.)। पुलिस ने शोपियां में आतंकी फंडिंग करने वाले एक नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने लश्कर-ए-तैयबा और द रेजिस्टेंस फ्रंट से जुड़े 10 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक, इस नेटवर्क के संबंध जम्मू-कश्मीर की अलग-अलग जेलों में बंद आतंकियों और उनके सहयोगियों से थे। मामले में और लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है।जांच में पता चला है कि आरोपी आम लोगों से चुपके से पैसे जुटाते थे।

इसके बाद इन पैसों को वित्तीय नेटवर्क के जरिए आतंकियों तक पहुंचाया जाता था, ताकि उनकी गतिविधियों में मदद की जा सके। जम्मू-कश्मीर में पिछले 68 दिनों में 28 आतंकी सहयोगी गिरफ्तार किए गए। गिरफ्तार किए गए आरोपी शोपियां, पुलवामा और कठुआ के रहने वाले हैं गिरफ्तार आरोपियों में शोपियां के सैदपोरा बाला के ओवैस शफी नाइकू, रावलपोरा के तजामुल अहमद शाह, चित्रगाम कलां के मोज इरबाल और इमदाद यूसुफ गनई शामिल हैं। इसके अलावा पुलवामा के मुर्रन के साकिब जहूर वानी और लियाकत नजीर लोन, अरमोह के आमिर अहमद गनई, शोपियां के ट्रेंज स्थित नादिगुंड के फिरदौस ठोकर और कठुआ के चेक हरिया के मोहम्मद हनीफ और काजू को भी गिरफ्तार किया गया है। ऑनलाइन लेनदेन की जांच में खुला आतंकी फंडिंग नेटवर्क पुलिस ने बताया कि जांच के दौरान अलग-अलग पेमेंट प्लेटफॉर्म से किए गए कई संदिग्ध ऑनलाइन लेनदेन का पता चला। इनकी जांच में आतंकी फंडिंग से जुड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ। इस मामले में शोपियां पुलिस स्टेशन में स्रङ्कक्र दर्ज की गई है। पुलिस के मुताबिक, आरोपी लोगों से लिए पैसे से आतंकियों को स्मार्टफोन और दूसरी जरूरी सुविधाएं मुहैया कराते थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है। नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान की जा रही है। पुलिस ने कहा कि इस मामले में और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। 2019 में आर्टिकल-370 हटने के बाद अस्तित्व में आया ञ्जक्रञ्ज जम्मू-कश्मीर के आतंकी संगठनों में 'द रजिस्टेंस फ्रंट' नया नाम है। 2019 में जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल-370 हटाए जाने के बाद यह अस्तित्व में आया। भारत सरकार भी मानती है कि ये लश्कर-ए-तैयबा का प्रॉक्सी आतंकी संगठन है। ये आतंकी संगठन जवानों और आम नागरिकों की हत्या के अलावा सीमा पार से ड्रग्स और हथियार की तस्करी में शामिल रहा है। सुरक्षा मामलों के जानकार बताते हैं कि सीमा पार से ड्डस्ठ्ठ हैंडलर्स ने ही लश्कर-ए-तैयबा की मदद से ञ्जक्रञ्ज को खड़ा किया।

कार्यालय नगर पंचायत बेलहरकला, जनपद-संत कबीरनगर

ई-प्रक्योरमेन्ट-निविदा सूचना

नगर पंचायत बेलहरकला, संत कबीर नगर द्वारा नगर क्षेत्र में पं, दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना के अन्तर्गत प्राप्